व्यापार

एक तरबूज के बदले वॉलमार्ट को 50 करोड़ का जुर्माना

वॉशिंगटन 13 नवम्बर (ए)। अमरीका के अलबामा राज्य में एक तरबूज के बदले 50 करोड़ का हर्जाना देने का मामला सामने आया है। वॉलमार्ट स्टोर को एक तरबूज के बदले ग्राहक को 75 लाख डॉलर यानी लगभग 50 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। एक पूर्व सैनिक हेनरी वॉकर वॉलमार्ट स्टोर में तरबूज लेने पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान वहां रखी लकड़ी में फंसकर वह गिर गए, जिससे उनकी कमर टूट गई। कोर्ट में हेनरी ने वॉलमार्ट पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि स्टोर लोगों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब एक कोर्ट ने वॉलमार्ट से पूर्व सैनिक को मुआवजा देने को कहा है। हालांकि वॉलमार्ट ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ आगे अपील करेंगे। वॉलमार्ट का कहना है कि उसके स्टोर में डिसप्ले बिल्कुल सुरक्षित था और वो उसमें कोई बदलाव नहीं करने जा रहा हैं। हफपोस्ट की खबर के मुताबिक, यह हादसा जून 2015 में हुआ था जब हेनरी वॉकर वॉलमार्ट स्टोर में तरबूज लेने गए थे।

Air Asia का बंपर ऑफर, ऑटो से भी कम किराए में लीजिए हवाई यात्रा का मजा

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। अगर आप देश-विदेश में हवाई जहाज से सफर करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। किफायती विमानन सेवाएं देने वाली मलेशियाई कंपनी एयर एशिया ने एक तरफ की यात्रा पर छूट की पेशकश की है। इसके तहत उसके स्थानीय संयुक्त उपक्रम नेटवर्क पर घरेलू यात्रा का टिकट 99 रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का टिकट 444 रुपए के मूल किराए पर उपलब्ध होगा। कंपनी ने जारी बयान में कहा कि इस पेशकश के तहत टिकटों की बुकिंग आज से शुरू होगी और ये टिकट अगले साल मई से जनवरी 2019 के बीच की यात्रा के लिए उपलब्ध होंगे। उसने कहा, ''घरेलू उड़ानों के लिए 99 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 444 रुपए के मूल किराए का लुत्फ उठाइए।'' उल्लेखनीय है कि विमान किराए में बड़ा हिस्सा ईंधन अधिभार, हवाई अड्डा शुल्क, कर एवं अन्य शुल्कों का होता है। एयर एशिया इंडिया एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें टाटा संस की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत और एयर एशिया की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

गलत ऑप्रेशन से किडनी हुई बेकार, नर्सिंग होम देगा जुर्माना

उदयपुर 13 नवम्बर (ए)। सरदारपुरा स्थित कल्पना नर्सिंग होम प्रबंधन पर एक महिला की किडनी का गलत ऑप्रेशन करने पर 3 साल पहले 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था जिसे राज्य उपभोक्ता फोरम ने यथावत रखते हुए जुर्माना राशि में 11,000 रुपए की बढ़ौतरी करने का आदेश दिया है। शहर के हाथीपोल क्षेत्र में पन्नाधाय मार्ग निवासी खातून पत्नी अल्ताफ हुसैन किडनी में पथरी की शिकायत लेकर कल्पना नर्सिंग होम में गई थी। अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि डा. गाडगिल अहमदाबाद में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाएंगे इसलिए मौजूद डाक्टरों की टीम सफलतापूर्वक ऑप्रेशन कर देगी। डा. आशीष, डा. शेखर और डा. जावेद ने खातून बेगम की सर्जरी की। उसे बताया गया कि किडनी में इन्फैक्शन होने के कारण स्टेंट डाल दिया गया है। सर्जरी के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। उसने बताया कि उसे फीस की रसीद और डिस्चार्ज टिकट नहीं दिया गया। घर जाते ही खातून बेगम को पीड़ा हुई। खातून ने किसी अन्य अस्पताल में डाक्टर से जांच करवाई तो उसने किडनी में स्टेंट गलत तरीके से लगाने से किडनी फेल होने की जानकारी दी। आयोग के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार चावला ने बताया कि कल्पना नर्सिंग होम के एम.डी. डा. सुनील चुघ ने सफाई दी थी लेकिन मंच और राज्य उपभोक्ता फोरम ने नर्सिंग होम को दोषी माना तथा 3 साल पहले हुए फैसले को यथावत रखते हुए उसे जुर्माना भी लगाया।

मिलेगी और राहत, जीएसटी के 5 व 12% स्लैब में भी होंगे बदलाव

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। सरकार ने जी.एस.टी. की दरों में बदलाव किया है, जिसके तहत उसने 178 वस्तुओं को 28 फीसदी के जी.एस.टी. स्लैब्स से हटाकर 18 फीसदी के स्लैब में डाल दिया है। चीजें सस्ती होने से खासकर लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार की योजना अब 5 और 12 फीसदी टैक्स स्लैब वाली चीजों को सस्ता करने की भी है। जी.एस.टी. परिषद की अगली कुछ बैठकों का टॉप अजेंडा यही हो सकता है। सीमेंट और पेंट जैसे कुछ वस्तुओं पर रेट अब भी 28 फीसदी के सबसे ऊंचे स्लैब में है। अगर टैक्स रेवेन्यू जोरदार रहा तो ऐसे कुछ वस्तुओं को भी निचले स्लैब में लाया जा सकता है।

18 फीसदी वाला स्लैब अब सबसे बड़ा: एक राज्य सरकार के उच्च अधिकारी ने बताया कि अब रियल ऐस्टेट और पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जी.एस.टी. के दायरे में लाने के मुद्दे पर भी परिषद विचार कर सकती है। पिछले हफ्ते गुवाहाटी में जी.एस.टी. परिषद की मीटिंग में किए गए बदलाव के निर्णय के बाद 18 फीसदी वाला स्लैब सबसे बड़ा हो गया है। तकरीबन आधी वस्तुएं और अधिकतर सेवाएं इस स्लैब के तहत आ गई हैं। बैठक में 178 वस्तुओं को 28 फीसदी से 18 फीसदी वाले स्लैब में लाने का निर्णय किया गया था। साथ ही, रेस्त्रां पर जी.एस.टी. को घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला भी किया गया था। इन कदमों से टैक्स रेवेन्यू 20 हजार करोड़ रुपए कम हो जाएगा।

सरकार को होगा 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान: कुछ और वस्तुओं को 28 फीसदी से 18 फीसदी वाले स्लैब में लाने से रेवेन्यू का कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था। अधिकारियों ने कहा कि सीमेंट और पेंट को निचले स्लैब में लाने पर ही सरकार को 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ता। 28 फीसदी वाले स्लैब में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और डिजिटल कैमरे जैसी आम उपयोग की चीजें बची रह गईं हैं। 28 फीसदी वाले स्लैब में अभी 50 से ज्यादा वस्तुएं हैं।

भारतनेट के सेकेंड फेज में टेलीकॉम फर्मों को 93600 करोड़ की सब्सिडी

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। सरकार ने सोमवार को लॉन्च हो रहे भारतनेट प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के तहत ग्रामीण इलाकों में वाई-फाई सर्विस मुहैया कराने के लिए भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर और रिलायंस जियो जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को 3600 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। टेलीकॉम कंपनियों को सब्सिडी की यह रकम वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर दी जाएगी। भारतनेट के तहत 11,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे फेज डू के इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके तहत देश के एक लाख ग्राम पंचायतों को नेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सरकार ने कुल 34,000 करोड़ रुपये के निवेश से बन रही इस योजना को दूसरे चरण में विस्तार देते हुए मार्च 2019 तक डबल करके 20 लाख किलोमीटर करने का प्लान बनाया है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड सरकार के साथ करार करेगा, जो भारतनेट का दूसरा फेज अपने निवेश से शुरू करेंगे जिसमें केंद्र सरकार की आंशिक वित्तीय मदद होगी। टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को मार्च 2019 तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने के लिए सोमवार से भारतनेट का दूसरा फेज शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट के साल के अंत तक पूरा होनेवाले पहले फेज में एक लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेटर गांव घर में कम से कम 2एमबीपीएस स्पीड देंगे।

फ्री कॉल, सस्ते डेटा के बाद अब नए मोर्चे पर जुटीं टेलिकॉम कंपनियां

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स के अच्छे दिन बने रहेंगे। फिलहाल डेटा के दाम बहुत सस्ते हो गए हैं। ज्यादातर प्लांस में कॉल भी फ्री हो गए हैं। आने वाले समय में यूजर्स को और भी सौगातें मिल सकती हैं। टेलिकॉम कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाने और उनको साथ बनाए रखने के लिए ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स के साथ ज्यादा से ज्यादा करार करेंगी। यह बायर्स और सेलर्स, दोनों ही साइड के लिए फायदेमंद होगा। मोबाइल फोन कंपनियों, ऐनालिस्ट्स और इस सेक्टर के जानकारों के मुताबिक, टेलिकॉम सर्विस प्रवाइडर्स स्मार्टफोन और डेटा यूज बढ़ाने के लिए ज्यादा कंज्यूमर्स हासिल करने के लिए हैंडसेट मेकर्स के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, लेकिन नए कस्टमर्स बनाने और रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उनको रिलायंस जियो का तरीका अपनाना होगा। जियो ने पिछले हफ्ते सब्सक्राइबर्स को कैश बैक और डिस्काउंट ऑफर कर नया मोर्चा खोल दिया। उसने

ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कंज्यूमर्स के लिए कुछ डिजिटल वॉलिट्स और एक ट्रैवल पोर्टल के जरिए यह ऑफर पेश किया। इंटरनैशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आइडीसी) इंडिया के सीनियर ऐनलिस्ट नवकेंद सिंह ने कहा, मेरे हिसाब से दूसरी टेलिकॉम कंपनियां वैसी ही स्कीम न सही, उसके जैसा प्लान जरूर ला सकती हैं क्योंकि टेलिकॉम कंपनियों पर कॉम्पिटिशन और टैरिफ का प्रेशर पड़ रहा है। मिसाल के लिए एयरटेल ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जहां वह फोन भी बेच रहा है। यह जियो जैसे प्लांस ला सकता है और यह पोस्ट पेड प्लांस और पेमेंट बैंक के जरिए पहले से ही कैशबैक दे रहा है। टेक्नोपाक एडवाइडर्स के सीएमडी अर्विंद सिंघल ने कहा कि वॉइस फ्री हो गया है और डेटा टैरिफ बहुत घट गया है।

200 से ज्यादा उत्पादों की एमआरपी में करना पड़ेगा बदलाव

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। करीब 200 उत्पादों के जीएसटी रेट में हुए बदलाव के बाद अब मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के पास पड़े लाखों करोड़ रुपये के स्टॉक की एमआरपी बदलने की चुनौती आ खड़ी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से पैकेज्ड कमोडिटीज पर रिवाइज्ड एमआरपी वाले स्टिकर लगाकर उन्हें कम से कम 31 मार्च तक बेचने की मांग की है। पैकेज्ड कमोडिटी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत किसी भी पैक पर प्रिंटेड एमआरपी का होना अनिवार्य है, जिसमें सभी टैक्सेज शामिल होने चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर कहा है कि देशभर में ट्रेडर्स के पास करीब 9 लाख करोड़ रुपये का स्टॉक है, जिसमें 6 लाख करोड़ का मामल पैकेज्ड हालत में है। इतने बड़े पैमाने पर रेट कट के बाद कीमत और एमआरपी बदलने की जरूरत आ पड़ी है, लेकिन स्टॉक वाले माल को दोबारा पैकिंग और प्रिंटिंग संभव नहीं है।

पूंजी मिलने पर सरकारी बैंक एमएसएमई क्षेत्र को कर्ज बढ़ाएंगे : अरुण जेटली

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए और पूंजी से वे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एम.एस.एम.ई.) को अधिक कर्ज दे पाएंगे। इससे निजी निवेश का 'तीसरा इंजन' चालू हो सके और आर्थिक वृद्धि तेज हो सके और रोजगार के नए अवसर बढ़ें। गौरतलब है कि फंसे कर्ज (एन.पी.ए.) से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के इरादे से पिछले महीने सरकार ने दो साल की एक वृहद योजना पेश की जिसमें 2.11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी उनमें डाली जाएगी। इसमें पुन: पूंजीकरण बांड तथा बजटीय समर्थन शामिल हैं। वृद्धि के इंजन के रूप में सार्वजनिक निवेश और एफ.डी.आई. (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रवाह बढ़ा है लेकिन तीसरा इंजन (निजी निवेश) अब भी कम है। जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक 'पीएसबी मंथन' को संबोधित

करते हुए कहा, ''सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन खर्च कर रही है और विदेशी निवेश आ रहा है।'' उन्होंने कहा, ''हमें तीसरे इंजन (निजी निवेश) में तेजी, मजबूत निजी क्षेत्र तथा एमएसएमई क्षेत्र की जरूरत है ताकि संभावना के अनुसार हम अनुकूलम वृद्धि दर हासिल कर सकें।'' उन्होंने कहा कि बैंक जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना है, उसमें एक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देना शामिल है क्योंकि क्षेत्र रोजगार सृजित कर रहा है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा हैं जबकि उसकी बांड बाजार या अंतरराष्ट्रीय वित्त तक पहुंच नहीं है। जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक 'पीएसबी मंथन' को यहां संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बजट से, बांड निर्गम और बैंकों की शेयर पूंजी के विस्तार के जरिए उनमें और पूंजी डालने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एक तरह से देखा जाए तो बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिये देश उन्हें पैसा दे रहा है। वित्त मंत्री ने बैंक प्रमुखों को आश्वस्त किया कि आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि हम वाणिज्यिक लेन-देन में हस्तक्षेप कर रहे हैं लेकिन जब व्यवस्था ये सब बदलाव कर ही और बैंकों को मजबूत करने के लिए ये सभी मौद्रिक योगदान दिए जा रहे हैं तो चाहते है कि सरकारी बैंकिंग प्रणाली खूब मजबूत हो ताकि वह आर्थिक वृद्धि मदद देने की आपकी क्षमता स्वयं ऊंची हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति जून 2017 को बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रुपए हो गई जो मार्च 2015 में 2.78 लाख करोड़ रुपए थी।

कहां गया मैकडोनाल्ड्स का सुनहरा 'एम'

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। मैकडोनाल्ड्स ब्रांड का सबसे अधिक दिखने वाला निशान 'एम' अब कुछ बाजारों में उसके उत्पादों से गायब हो चुका है। पिछले करीब एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकतर मैकडोनाल्ड्स रेस्तरां बिना 'एम' चिन्ह वाले पैर के साथ अपने बर्गर, गर्म एवं शीतल पेय की बिक्री कर रहे हैं। हालांकि अंतिम बिल पर वह अभी भी मौजूद है। इसके अलावा नियामकीय अनुपालन के साथ-साथ उत्पादों में कटौती का भी मामला है। प्रमुख जगहों पर मौजूद कम्पनी के आऊटलेट जैसे मध्य दिल्ली में आई.टी.ओ. मैट्रो स्टेशन के समीप मैकडोनाल्ड्स आऊटलैट में 'सॉफ्ट सर्व्स पर हमेशा 'सोल्ड आऊट' लिखा होता है। दूध के आपूर्तिकर्ता के साथ समस्याओं के कारण वहां कभी-कभी हॉट बेवरेजेस भी उपलब्ध नहीं होते लेकिन कोल्ड कॉफी आप जरूर ले सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही तैयार होती

है। विक्रम बख्शी को इसी साल मैकडोनाल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईपीएल) के साथ उनकी बराबर हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम कनाट प्लाजा रैस्टोरैंट्स प्राइवेट लिमिटेड का दोबारा प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

ब्रांडिंग के साथ वस्तुओं की आपूर्ति रोकने के लिए जारी किया नोटिस: उन्होंने कहा, ''हमारे पैकेजिंग आपूर्तिकर्ताओं को मैकडोनाल्ड्स कार्पोरेशन द्वारा उसके ब्रांडिंग के साथ वस्तुओं की आपूर्ति रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वे छोटे-मोटे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमें आपूर्ति करना बंद कर दिया है इसलिए कुछ मामलों में हम बर्गर, फाइस आदि को बिना लोगो वाले सादे पैकिंग में परोस रहे हैं। हालांकि उन स्टोरों में मैकडोनाल्ड्स नाम का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और उनके उत्पाद भी बिल्कुल समान हैं।''

सांझेदारों के बीच नहीं बन पाई कोई सहमति: वर्ष 2014 के आरंभ में बख्शी ने 150 करोड़ रुपए की शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर संयुक्त उद्यम में मैकडोनाल्ड्स की हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की थी। इस पर अमरीकी कम्पनी ने 48 से 50 करोड़ रुपए में बख्शी की हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर दी। बाद में उचित बाजार मूल्य पर हिस्सेदारी बिक्री की पेशकश की गई और बख्शी की हिस्सेदारी के लिए पहले 2500 करोड़ रुपए और बाद में 1800 करोड़ रुपए की पेशकश की गई लेकिन दोनों सांझेदारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। इस वर्ष जुलाई में नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) ने बख्शी को कनाट प्लाजा रैस्टोरैंट्स प्राइवेट लिमिटेड में दोबारा प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का आदेश दिया।

पेट्रोनेट ने मूंदड़ा एलएनजी प्लांट में हिस्सेदारी लेने का प्लान छोड़ा

नई दिल्ली 13 नवम्बर (ए)। पेट्रोनेट एलएनजी ने गुजरात में जीएसपीसी के लगभग पूरे हो चुके 4500 करोड़ रुपये के एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल में 25 पर्सेंट स्टेक लेने का प्लान कैंसल कर दिया है ताकि उसकी प्रमोटर आईओसी इस कंपनी में बड़ा स्टेक ले सके। पब्लिक सेक्टर की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 50 लाख टन सालाना कैपेसिटी वाले मूंदड़ा इंपोर्ट टर्मिनल में आधी हिस्सेदारी लेने के लिए पिछले दो साल से गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से बातचीत कर रही थी। देश की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट एलएनजी ने इसी साल कंपनी में स्टेक लेने में दिलचस्पी लेना शुरू किया था। अब वह तमिलनाडु के एक्लोर में आईओसी की 50 लाख टन कैपेसिटी वाली अंडर कंस्ट्रक्शन एलएनजी इंपोर्ट फैसिलिटी में स्टेक लेना चाहती है। पेट्रोनेट एलएनजी के एक अफसर ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा, हमने मूंदड़ा में स्टेक खरीदने के प्लान पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है क्यों हमारी प्रमोटर कंपनी उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही है।

पेट्रोनेट चाहती है कि आईओसी उसको मूंदड़ा के बदले अपने एक्लोर टर्मिनल में 25 पर्सेंट स्टेक खरीदने का मौका दे। सूत्र ने कहा, हमारे लिए एक्लोर रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हमारे पास गुजरात के दाहेज और केरल के कोच्चि में पश्चिमी तट पर पहले से ही दो टर्मिनल हैं। एक्लोर के लिए बातचीत जारी है। जीएसपीसी ने पहले आईओसी को 50 पर्सेंट स्टेक खरीदने का ऑफर दिया था लेकिन कंपनी तब 25-26 पर्सेंट से ज्यादा हिस्सा लेने को इच्छुक नहीं थी।

बेनामी संपत्ति पर मोदी सरकार का शिकंजा, आसमानी आंख से होगी छानबीन

भोपाल 13 नवम्बर (ए)। नोटबंदी और जी.एस.टी. के बाद मोदी सरकार का अगला निशाना बेनामी संपत्ति है। बेनामी संपत्ति की जांच के लिए आयकर विभाग पहली बार इसरो की मदद लेगा। इस मुहिम में देश की अन्य जांच एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सी.बी.डी.टी.) ने यह प्रयोग गुजरात और राजस्थान में कराया, जिसके अच्छे नतीजे निकले। अब मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में भी आसमानी आंख से बेनामी संपत्तियों की खोजबीन शुरू होगी।

जांच एजेंसियां करेंगी मदद

आयकर विभाग ने एक बेनामी प्रॉपर्टी यूनिट भी बनाई है, जहां ऐसी सभी संवेदनशील सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), सीबीआई, फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (एफआईयू), डायरेक्टोरेट आफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की सेवाएं भी ली जाएंगी। इन एजेंसियों के जरिए विभाग देशभर से भारी भरकम संदिग्ध लेनदेन, हवाला और मुखौटा कंपनियों की गतिविधियों का ब्योरा भी जुटाएगा।

ऐसे होगी छानबीन

किसी भी क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज के क्लोज व्यू

का पहले लोकल नेटवर्क और भूमि रिकॉर्ड (खसरा नंबर) से मिलान होगा। इसके बाद उस इमेज से संबंधित भूमि के मालिक का नाम-पता लेकर विभागीय अफसर जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे। खसरे में 14 बिन्दुओं की जानकारी रहती है। पंजीयन विभाग से रजिस्ट्री का ब्योरा लेकर भूमि मालिक की आर्थिक स्थिति का आकलन और पिछले 15 साल के रिकॉर्ड की छानबीन होगी। भूमि मालिक की आर्थिक हैसियत का परीक्षण भी होगा। इससे प्रॉपर्टी की असली कहानी सामने आ जाएगी। सैटेलाइट की आंख से आयकर विभाग अब यह जानकारी भी हासिल कर सकेगा कि किसी खेती की जमीन पर कब, कौन-सी फसल ली गई। पिछले वर्षों की इमेज भी सुरक्षित मिल जाएगी। इसी तरह अंदरूनी क्षेत्र में किसी प्रॉपर्टी का वास्तविक क्षेत्रफल क्या है, यह भी सैटेलाइट मिनटों में बता देगा।